

देर आयद, दुष्ट आयद

संसद के मानसून सत्र के अधिकारी दिन ऑनलाइन गेमिंग बिल को गज्जस्याम में पास कर दिया गया। सरकार को देर से ही सही, लेकिन लोगों के पैसों को सुरक्षित रखने के लिए बिल लाना ही पड़ा, क्योंकि यह लत देश के लोगों की आर्थिक स्थिति को खाराव कर रही थी, जिसकी वजह से हर चौथे घर में झगड़े होते रहते हैं। अब देखना यह है कि सरकार इस बिल को किस प्रकार अमल में लाती ही और इसकी जिम्मेदारी किसको दी जाती है। अगर इस बिल का सही कियान्वयन हआ, तो यह लोगों के लिए अच्छा साबित होगा और किसी ऐसे अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी दी गई, जो आष्ट्राचार के आकंठ में डूबा हुआ है, तो इस बिल की आड़ में और ज्यादा भ्रष्टाचार पनपन लगेगा, इसलिए सरकार को सोचें-समझकर कदम उठाना है।

सत्र की शुरुआत 21 जुलाई से हुई थी। दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को छोड़कर इस सत्र में बहुत कम कामकाज हुआ है। एक महीने लंबे सत्र के दौरान लोकसभा ने 12 और गज्जस्याम ने 15 विधेयक पास किए, लेकिन बार-बार व्यवस्था, स्थान और बायकॉट जारी रहा। अधिकारी दिन की कार्यवाही के दौरान सदन में 102 देर चर्चा का समय विधिरित किया गया था, लेकिन सिर्फ 37 घंटे ही संख्या ही बची है। यह एक व्यक्ति, एक बोट के सिद्धांत का व्यावहारिक रूप है।

भारत का चुनाव आयोग ECI, जिसे वित्तनं और नियक्ष चुनाव कराने का संवैधानिक तावियल सौंपा गया है, दशकों में इस जिम्मेदारी का नियम तरह बदल रहा है। इसके अन्तर्गत आयोग का यह खुलापन संघर्ष विशेष रूप से हमारे जैसे विशाल और विविध देश में, जहाँ मतदाताओं की संख्या 96 करोड़ से अधिक है, मतदाता सूची का सटीक और निरंतर अद्यतन एक असाधारण ताकिंग और लोकतांत्रिक अध्यास है। यह एक

पारदर्शिता हमेशा से चुनाव आयोग का

आपात्तियों के लिए खुली रहती है, अतिरिक्त लोकतंत्र के बाग लेने का अवसर दिया जाता है। चुनाव आयोग का यह खुलापन संघर्ष विशेष रूप से से भारी सार्वजनिक भूमियों द्वारा 2000-2009 के बीच किए गए सर्वेक्षणों में, चुनाव आयोग को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक संस्था पाया

गया, जिसकी विश्वसनीयता 85-87 प्रतिशत तक

रही। 2007 का एक महत्वपूर्ण प्रयोग SAD

मतदाता,

मतदाता सूची प्रबंधन में सबसे

उल्लेखनीय प्रयोगों में से एक 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान हुआ है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेलिपिंग सोसाइटी CSDS द्वारा 2000-2009 के बीच किए गए सर्वेक्षणों में, चुनाव आयोग को भारत की सबसे भरोसेमंद

सार्वजनिक संस्था पाया

पहुंच, जिसे संघर्ष हुआ कि यह व्यावहारिक रूप से बदला जाए। इसकी विश्वसनीयता 85-87 प्रतिशत तक

रही। 2007 का एक महत्वपूर्ण प्रयोग SAD

मतदाता,

मतदाता सूची प्रबंधन में सबसे

उल्लेखनीय प्रयोगों में से एक 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान हुआ है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेलिपिंग सोसाइटी CSDS द्वारा 2000-2009 के बीच किए गए सर्वेक्षणों में, चुनाव आयोग को भारत की सबसे भरोसेमंद

सार्वजनिक संस्था पाया

गया, जिसकी विश्वसनीयता 85-87 प्रतिशत तक

रही। 2007 का एक महत्वपूर्ण प्रयोग SAD

मतदाता,

मतदाता सूची प्रबंधन में सबसे

उल्लेखनीय प्रयोगों में से एक 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान हुआ है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेलिपिंग सोसाइटी CSDS द्वारा 2000-2009 के बीच किए गए सर्वेक्षणों में, चुनाव आयोग को भारत की सबसे भरोसेमंद

सार्वजनिक संस्था पाया

गया, जिसकी विश्वसनीयता 85-87 प्रतिशत तक

रही। 2007 का एक महत्वपूर्ण प्रयोग SAD

मतदाता,

मतदाता सूची प्रबंधन में सबसे

उल्लेखनीय प्रयोगों में से एक 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान हुआ है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेलिपिंग सोसाइटी CSDS द्वारा 2000-2009 के बीच किए गए सर्वेक्षणों में, चुनाव आयोग को भारत की सबसे भरोसेमंद

सार्वजनिक संस्था पाया

गया, जिसकी विश्वसनीयता 85-87 प्रतिशत तक

रही। 2007 का एक महत्वपूर्ण प्रयोग SAD

मतदाता,

मतदाता सूची प्रबंधन में सबसे

उल्लेखनीय प्रयोगों में से एक 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान हुआ है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेलिपिंग सोसाइटी CSDS द्वारा 2000-2009 के बीच किए गए सर्वेक्षणों में, चुनाव आयोग को भारत की सबसे भरोसेमंद

सार्वजनिक संस्था पाया

गया, जिसकी विश्वसनीयता 85-87 प्रतिशत तक

रही। 2007 का एक महत्वपूर्ण प्रयोग SAD

मतदाता,

मतदाता सूची प्रबंधन में सबसे

उल्लेखनीय प्रयोगों में से एक 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान हुआ है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेलिपिंग सोसाइटी CSDS द्वारा 2000-2009 के बीच किए गए सर्वेक्षणों में, चुनाव आयोग को भारत की सबसे भरोसेमंद

सार्वजनिक संस्था पाया

गया, जिसकी विश्वसनीयता 85-87 प्रतिशत तक

रही। 2007 का एक महत्वपूर्ण प्रयोग SAD

मतदाता,

मतदाता सूची प्रबंधन में सबसे

उल्लेखनीय प्रयोगों में से एक 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान हुआ है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेलिपिंग सोसाइटी CSDS द्वारा 2000-2009 के बीच किए गए सर्वेक्षणों में, चुनाव आयोग को भारत की सबसे भरोसेमंद

सार्वजनिक संस्था पाया

गया, जिसकी विश्वसनीयता 85-87 प्रतिशत तक

रही। 2007 का एक महत्वपूर्ण प्रयोग SAD

मतदाता,

मतदाता सूची प्रबंधन में सबसे

उल्लेखनीय प्रयोगों में से एक 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान हुआ है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेलिपिंग सोसाइटी CSDS द्वारा 2000-2009 के बीच किए गए सर्वेक्षणों में, चुनाव आयोग को भारत की सबसे भरोसेमंद

सार्वजनिक संस्था पाया

गया, जिसकी विश्वसनीयता 85-87 प्रतिशत तक

रही। 2007 का एक महत्वपूर्ण प्रयोग SAD

मतदाता,

मतदाता सूची प्रबंधन में सबसे

उल्लेखनीय प्रयोगों में से एक 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान हुआ है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेलिपिंग सोसाइटी CSDS द्वारा 2000-2009 के बीच किए गए सर्वेक्षणों में, चुनाव आयोग को भारत की सबसे भरोसेमंद

सार्वजनिक संस्था पाया

गया, जिसकी विश्वसनीयता 85-87 प्रतिशत तक

रही। 2007 का एक महत्वपूर्ण प्रयोग SAD

मतदाता,

मतदाता सूची प्रबंधन में सबसे

उल्लेखनीय प्रयोगों में से एक 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान हुआ है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेलिपिंग सोसाइटी CSDS द्वारा 2000-2009 के बीच किए गए सर्वेक्षणों में, चुनाव आयोग को भारत की सबसे भरोसेमंद

सार्वजनिक संस्था पाया

गया, जिसकी विश्वसनीयता 85-87 प्रतिशत तक

रही। 2007 का एक महत्वपूर्ण प्रयोग SAD

मतदाता,

मतदाता सूची प्रबंधन में सबसे

उल्लेखनीय प्रयोगों में से एक 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान हुआ है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेलिपिंग सोसाइटी CSDS द्वारा 2000-2009 के बीच किए गए सर्वेक्षणों में, चुनाव आयोग को भारत की सबसे भरोसेमंद

सार्वजनिक संस्था पाया

गया, जिसकी विश्वसनीयता 85-87 प्रतिशत तक

रही। 2007 का एक महत्वपूर्ण प्रयोग SAD

मतदाता,

